शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 14 – 21 सितम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

नए सीएम कार्यालय पर सियासत तेज

शिमला/शैल। । राजधानी शिमला के एलर्सली फेस-II में नए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन के बाद इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नये कार्यालय का उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि यह कार्यालय केवल मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले सभी मुख्यमंत्रियों के लिए होगा। वहीं विपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस पर खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री का कहना है कि पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह कम थी। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। उनके बैठने और इन्तजार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। नए कार्यालय में लोगों के लिए वेटिंग एरिया, बैठक के लिए हॉल, अधिकारियों के कमरे और पार्किंग जैसी सुविधाएं रखी गई हैं। सरकार के अनुसार इससे मुख्यमंत्री और आम लोगों के बीच मुलाकात आसान होगी और सरकारी कामकाज और भी बेहतर तरीके से चल सकेगा।

नए कार्यालय में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी कमरे बनाये गए हैं। नए भवन में करीब 40 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होने की भी जानकारी दी गई है। इस कार्यालय की अनुमानित लागत करीब 19.72 करोड़ रुपये बताई गई थी।

नए कार्यालय को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हिमाचल पहले से आर्थिक दबाव में है और सरकार को खर्च की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। विपक्ष का सवाल है कि जब प्रदेश पर कर्ज और दूसरे वित्तीय दायित्व बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे भवन पर इतना खर्च करना कितना जरूरी था। कुछ पेंशनरों ने भी इसी तरह के सवाल उठाते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार आर्थिक मुश्किलों की बात करती है और दूसरी तरफ नये भवन का उद्घाटन किया जा रहा है।

कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने इस मामले में इससे भी ज्यादा खर्च होने का आरोप लगाया है। उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा करते हुए भवन और फर्नीचर पर हुए खर्च पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार की ओर से बताई गई लागत करीब 20 करोड़ रुपये है। इसलिए 50 करोड़ रुपये के दावे की पुष्टि के लिए पूरा सरकारी खर्च और भुगतान का रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।

नए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर यह भी चर्चा है कि ऐसी सुविधा की जरूरत पहले की सरकारों में भी महसूस की गई थी। वर्ष 2021 में एलर्सली परिसर में मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए वेटिंग हॉल, लिफ्ट और रैंप तथा सचिवालय में पार्किंग और कार्यालय की सुविधा बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव सामने आये थे। इस मामले में उस समय एनजीटी और बाद में अदालत की प्रक्रिया भी हुई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी नये मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर विचार हुआ था। उनके अनुसार हेरिटेज से जुड़े कारणों से उस समय यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। मौजूदा भवन का निर्माण वर्तमान सरकार के समय आगे बढ़ा। वर्ष 2025 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद निर्माण का काम पूरा हुआ और अब मुख्यमंत्री कार्यालय यहां से काम करेगा।

इस मामले में एक कानूनी पहलू भी है। एलर्सली परिसर में हुए निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। इसमें निर्माण और हेरिटेज नियमों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है अंतिम स्थिति फैसले के बाद साफ होगी।

नए कार्यालय को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भवन की अंतिम लागत कितनी रही, इसमें कौन-कौन से काम शामिल हैं और इससे लोगों को वास्तव में कितनी सुविधा मिलती है। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता और खर्च दोनों का आकलन इसके वास्तविक इस्तेमाल से होगा।

किशाऊ समझौते में हिमाचल के पानी का हिसाब कौन देगा?

बिंदल ने सरकार से मांगा श्वेतपत्र

शिमला/शैल। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर छह राज्यों के समझौते के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हिमाचल में अब प्रदेश के जल अधिकारों और आर्थिक लाभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 15 सितंबर को हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र के अनुसार परियोजना के जल घटक की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी।

टौंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। समझौते में हिमाचल के लिए आवंटित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देने के बदले परियोजना के विद्युत घटक की लागत में दूसरे राज्यों की भागीदारी का प्रावधान है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से श्वेतपत्र मांगा है। उनका कहना है कि हिमाचल को अपनी बिजली हिस्सेदारी के लिए करीब 1,764 करोड़ रुपये लगाने पड़ते, जिसका सालाना वित्तीय भार लगभग 136 करोड़ रुपये बैठता। सवाल यह है कि इस खर्च को बचाने के बदले प्रदेश के दीर्घकालिक जल हितों पर क्या असर पड़ेगा।

बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के उस अनुमान का भी हवाला दिया है जिसमें किशाऊ से हिमाचल को करीब 1,200 करोड़ रुपये सालाना लाभ मिलने की बात कही गई है। उनका कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अनुमानित आय किस आधार पर है और पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार तथा पुनर्वास के लिहाज से प्रदेश को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा।

उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने समझौते को छह दशक पुराने गतिरोध का समाधान बताते हुए इसका श्रेय केंद्र सरकार के प्रयासों को दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और छह राज्यों की सरकारों के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया। उनके अनुसार केंद्र करीब 90 प्रतिशत वित्तीय भार उठाएगा और हिमाचल के विद्युत घटक की लागत में अन्य राज्यों की हिस्सेदारी से प्रदेश का बोझ घटेगा।

अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा समझौते को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच मूल मुद्दा परियोजना का श्रेय नहीं, बल्कि हिमाचल के पानी के बदले प्रदेश को मिलने वाला वास्तविक लाभ है।

सरकार को समझौते की शर्तें सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना होगा कि हिमाचल ने कितना पानी दिया, बदले में बिजली और आर्थिक हिस्सेदारी कितनी मिली तथा आने वाले वर्षों में प्रदेश को इसका कितना लाभ होगा। किशाऊ का फैसला दशकों तक असर डालने वाला है, इसलिए इसका मूल्यांकन केवल आज के वित्तीय बोझ से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जल अधिकार और आर्थिक हितों के आधार पर होना तय है।

युवा लोकतंत्र की मजबूती में निभाएं सक्रिय भूमिका : राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से संविधान के मूल्यों को समझने, लोकतांत्रिक परंपराओं



को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी महत्वपूर्ण भागीदार हैं।

जयपुर में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित भारतीय युवा संसद के 31वें राष्ट्रीय सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 26 राज्यों से आए विद्यार्थियों ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा कर लोकतांत्रिक संवाद की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। इसमें संवाद, सहमति-असहमति, भागीदारी और जवाबदेही भी जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय युवा संसद युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसे आपसी मनमुटाव में नहीं बदलना चाहिए। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।

भारत की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हाल में नई दिल्ली में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और रणनीतिक स्वायत्तता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

राज्यपाल ने युवाओं से जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित करने तथा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनने का आहवान किया।

गणेशोत्सव आध्यात्मिक विरासत, आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक : राज्यपाल

शिमला/शैल। मुंबई में आयोजित गणेशोत्संव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र



गुप्ता ने लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता और परिजनों के साथ प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री गणेश से देश और प्रदेश में शांति, सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गणेशोत्सव भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व आस्था, भक्ति, सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव सामाजिक और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करता है तथा देश में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है।

कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि लालबागचा राजा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और दशकों से यह मुंबई की धार्मिक आस्था तथा जनभागीदारी का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने गणेशोत्सव के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं तथा भगवान श्री गणेश से देश की प्रगति, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

भारत की समृद्ध परंपरा हमारी पहचान का आधार:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा देश की पहचान का महत्वपूर्ण



आधार है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के दौर में विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है।

राज्यपाल शनिवार शाम कांगड़ा जिले के सिद्धबाड़ी स्थित चिन्मय तपोवन आश्रम में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। यह कार्यक्रम चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस दौरान मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद के जीवन, शिक्षाओं और योगदान को याद किया गया।

राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को देश-विदेश में पहुंचाने के लिए चिन्मय मिशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में ज्ञान, सेवा, साधना और मानव कल्याण की समृद्ध परंपरा रही है। इन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि गीता मनुष्य को जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना के साथ मानव कल्याण के लिए काम करने का आहवान किया।

राज्यपाल ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवाओं को संस्कार, सेवा, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के साथ आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के अवसर भी उपलब्ध करवाने चाहिए।

कार्यक्रम में दलाई लामा का संदेश पढ़कर सुनाया गया। स्वामी मित्रनंद ने चिन्मय मिशन की 75 वर्षों की यात्रा और स्वामी चिन्मयानंद के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांगड़ा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, उपायुद्र हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

स्वास्थ्य विभाग में 228 डॉक्टरों की भर्ती शुरू

शिमला/शैल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है।

सरकार के अनुसार, भर्ती का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना और मरीजों को नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। नए पदों को मंजूरी दिए जाने से यह भी संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की जरूरत अभी बनी हुई है।

इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सहायक प्रोफेसर का एक पद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इसी माह सरकार 194 चिकित्सकों की नियुक्ति कर चुकी है। इनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठयक्रम और सीनियर रेजिडेंसी पूरी करने के बाद इन चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नई भर्तियों और नियुक्तियों से खाली पद भरने के साथ मौजूदा डॉक्टरों पर काम का दबाव कम होगा। सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है।

22 सितंबर से फिर शुरू होगा एग्री मशीनरी पोर्टल

शिमला/शैल। कृषि अभियान्त्रिकी उप मिशन के तहत अनुदान पर कृषि उपकरण लेने के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल 22 सितंबर से फिर सक्रिय होगा। किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in के माध्यम से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1 अक्तूबर को लॉटरी के माध्यम से किसानों का संबंधित कृषि उपकरणों के लिए चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वे केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों से ही कृषि उपकरण खरीदें और स्वीकृत मॉडल का ही चयन करें। इससे अनुदान प्राप्त करने में बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

विभाग के अनुसार पहाड़ी खेती को आसान बनाने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके तहत पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं।

मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने काबी तिंगदा वाइब्रेंट विलेज का दौरा किया

शिमला/शैल। सिक्किम के आधिकारिक दौरे पर गए हिमाचल प्रदेश के 11 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने काबी तिंगदा ब्लॉक प्रशासनिक केंद्र (बीएसी) और वाइब्रेंट विलेज का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सीमावर्ती क्षेत्र



में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली।

खंड विकास अधिकारी और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मीडिया दल का स्वागत किया। अधिकारियों ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इनमें सड़क और संपर्क व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तथा ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत करना है। इसके जरिए ग्रामीणों को अपने गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

खंड विकास अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को ग्रामीण विकास और स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने कार्यों से संबंधित जानकारी साझा की।

दौरे के दौरान हिमाचल और सिक्किम के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ। पीआईबी शिमला की ओर से काबी तिंगदा के खंड विकास अधिकारी को हिमाचली टोपी और मफलर भेंट किया गया।

मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने बाद में ऐतिहासिक काबी लुंगचोक का भी दौरा किया। यहां प्रतिनिधिमंडल ने लेपचा और भूटिया समुदायों के बीच हुए पारंपरिक 'ब्लड ब्रदरहुड' समझौते और इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस दौरे से उन्हें सिक्किम के सीमावर्ती गांवों में हो रहे विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझने का अवसर मिला।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

विभागीय परीक्षाएं 26नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे। इच्छुक कर्मचारी 17 अक्तूबर तक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्षों को आवेदनों का अनुमोदन 24 अक्तूबर तक करना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पेपर नंबर-1 की परीक्षा शिमला के राजकीय महाविद्यालय संजौली के अलावा राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडी में भी आयोजित की जाएगी।

परीक्षा के प्रवेश-पत्र उम्मीदवारों के मानव संपदा पोर्टल पर उनके खातों में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधूरा आवेदन मिलने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा।

परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की समय-सारणी विभागीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

किशाऊ परियोजना में हिमाचल पर 2000 करोड़ का बोझ टला

पानी का इस्तेमाल करने वाले राज्य उठाएंगे बिजली की लागत, हिमाचल को 211 मेगावाट बिजली और संभावित 1200 करोड़ सालाना आय

शिमला/शैल। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पर पड़ने वाले करीब 2000 करोड़ रुपये



के वित्तीय बोझ को टालने का दावा किया है। 15,624 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है।

समझौते की सबसे अहम शर्त बिजली की लागत को लेकर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के अनुसार, पहले परियोजना के बिजली घटक की लागत में हिमाचल को करीब 2000 करोड़ रुपये का हिस्सा देना था। पिछली सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी पर सहमति जताई थी। वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए हिमाचल पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का विरोध किया। अब मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना के पानी का इस्तेमाल करने वाले राज्य बिजली घटक की लागत वहन करेंगे।

इसके बदले हिमाचल को परियोजना से 211 मेगावाट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा अनुमान के अनुसार इससे राज्य को सालाना करीब 1200 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। पहले यह आय करीब 600 करोड़ रुपये आंकी गई थी। यानी राज्य सरकार के अनुसार परियोजना से हिमाचल को बिजली के साथ नियमित राजस्व भी मिलेगा।

किशाऊ परियोजना हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर टौंस नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भी समझौते में मुआवजे का प्रावधान है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड के कर्मचारियों की 50-50 प्रतिशत भागीदारी रखने की बात भी कही गई है।

सरकार का कहना है कि परियोजना में हिमाचल के जल अधिकारों और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जल संसाधनों से दूसरे राज्यों को लाभ मिलता है, इसलिए हिमाचल को भी उसका उचित आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।

सुक्खू ने यह मुद्दा भी उठाया कि हिमाचल को देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का आर्थिक मूल्य मिलना चाहिए। उनका कहना है कि प्रदेश जल, ग्लेशियर संरक्षण और स्वच्छ हवा जैसी सेवाएं देता है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं का आर्थिक नुकसान भी राज्य को झेलना पड़ता है।

अर्की में 34.46 करोड़ की सात विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले



के अर्की विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 34.46 करोड़ रुपये की सात विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 1.50 करोड़ रुपये से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरयांज के भवन, 1.02 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी के खेल मैदान, 1.81 करोड़ रुपये से फल एवं सब्जी उप-मंडी कुनिहार तथा 10.17 करोड़ रुपये से बने दाड़लाघाट आईएसबीटी बस स्टैंड का उद्घाटन किया।

उन्होंने 10.39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33/11 केवी, 315 एमवीए जीआईएस विद्युत उपकेंद्र ग्याणा (मांगू), 7.09 करोड़ रुपये की दानोघाट-साहजादा-नेरी प्लाटी संपर्क सड़क तथा 2.38 करोड़ रुपये की सिनटीघाट-बानधार एंबुलेंस सड़क का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कुनिहार फल एवं सब्जी उप-मंडी से करीब 25 से 30 ग्राम पंचायतों के किसानों को अपनी उपज के बेहतर विपणन और उचित दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ग्याणा विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र की करीब 10 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और कम वोल्टेज की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। विधायक संजय अवस्थी ने विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

अक्तूबर में क्लास-III पेंशनरों को 30 प्रतिशत और क्लास-I व II पेंशनरों को 15 प्रतिशत पेंशन एरियर मिलेगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास- III पेंशनरों को पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत और क्लास- I व II पेंशनरों को 15 प्रतिशत



एरियर अक्तूबर में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। सभी विभागों को लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का एरियर पहले ही जारी किया जा चुका है। सरकार महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के समय प्रदेश पर करीब 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों-पेंशनरों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। उन्होंने दावा किया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश को हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से पूछे पेपर लीक और स्वच्छता पर सवाल

रैल स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने किया विद्यार्थियों से संवाद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नादौन क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल के विद्यार्थियों से संवाद किया। विद्यार्थियों ने पढ़ाई, करियर, स्वच्छता और पेपर लीक सहित स्कूल की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किए।

एक छात्रा ने पूछा कि समाज में सफाई के काम को छोटा क्यों माना जाता है। उसने कजाकिस्तान की बेहतर स्वच्छता व्यवस्था का उदाहरण देते हुए हिमाचल को भी साफ और हरा-भरा बनाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने घर के साथ आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

विद्यार्थियों ने सीबीएसई पाठयक्रम को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि नया पाठयक्रम रुचिपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगा।

एक छात्र ने नीट पेपर लीक का मामला उठाते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में प्रश्नपत्र लीक और बिक्री के मामलों में जांच के बाद तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अब राज्य चयन आयोग में मेरिट के आधार पर चयन किया जा रहा है और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

विद्यार्थियों ने रंगस से स्कूल के लिए बस सुविधा की मांग भी रखी। वहीं, प्राथमिक स्कूल की टूटी सीढ़ियों की समस्या पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द मरम्मत के निर्देश दिए।

विधवाओं के बच्चों को 27 वर्ष तक मिलेंगे 1000 रुपये मासिक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों को 27 वर्ष



की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए हैं। अभी योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को यह राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने को कहा, ताकि पात्र लाभार्थियों को आवेदन और लाभ लेने में परेशानी न हो। योजना के तहत वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने योजना के 50 मेधावी विद्यार्थियों और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के 50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए।

बैठक में प्रस्तावित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नौ बाल देखभाल केंद्रों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कांगड़ा के लुथान में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय ग्राम परिसर का निर्माण मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए।

ड्रग तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कारवाई की सराहना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कारवाई और नशे के कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई करीब 4.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने के लिए शिमला पुलिस की सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ड्रग कारोबार के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना भी जरूरी है। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई वित्तीय जांच की सराहना की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से जुड़ी 12.52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस को ड्रग तस्करों के नेटवर्क और उनके आर्थिक आधार को कमजोर करने के लिए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।

बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

बढ़ते कर्ज से दशकों की वित्तीय नीतियों पर उठे सवाल



हिमाचल प्रदेश की कर्ज कहानी को किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल के खाते में डालकर खत्म नहीं किया जा सकता। यह दशकों में लिए गए आर्थिक फैसलों, विकास की प्राथमिकताओं और सरकारी खर्च की नीतियों का परिणाम है। इसलिए अब सवाल केवल यह नहीं कि प्रदेश पर कितना कर्ज है, बल्कि यह है कि दशकों की उधारी से हिमाचल ने क्या हासिल किया और अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता क्यों नहीं बना पाया।

समय के साथ हिमाचल में सड़क नेटवर्क बढ़ा, बिजली परियोजनाएं बनीं, उद्योग आए, पर्यटन और बागवानी का विस्तार हुआ तथा सरकारी संस्थानों का ढांचा मजबूत हुआ। प्रदेश के पास अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार आर्थिक गतिविधि और राजस्व पैदा करते हैं। इसके बावजूद यदि सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों के लिए लगातार नई उधारी की जरूरत पड़ रही है तो सवाल विकास की मात्रा से ज्यादा उसकी वित्तीय गुणवत्ता पर उठता है। किसी परियोजना की सफलता केवल उसके निर्माण से तय नहीं होती। यह भी देखना जरूरी है कि उससे कितनी आर्थिक गतिविधि, रोजगार, उत्पादन या सरकारी आय बढ़ी। हर सरकार को कर्ज के उपयोग और परिणाम का हिसाब देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उससे बनी परिसंपत्तियां कितना आर्थिक लाभ दे रही हैं और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नई उधारी प्रदेश की आय बढ़ाने में कितनी भूमिका निभाएगी।

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हिमाचल में समय-समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गईं। उद्योगों को जमीन, बिजली और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लेकिन इस वित्तीय नीति से प्रदेश को कितना स्थायी राजस्व मिला। उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों के मुकाबले राज्य की अपनी आय कितनी मजबूत हुई इसका भी मूल्यांकन जरूरी है।

जलविद्युत के मामले में भी यही सवाल है। मुद्दा बिजली परियोजनाओं की उपयोगिता नहीं, बल्कि बिजली से मिली आय के दीर्घकालीन प्रबंधन का है। क्या इस आय को ऐसी परिसंपत्तियों में लगाया गया, जो भविष्य में और आय पैदा करतीं?

कर्ज तब गंभीर चुनौती बनता है जब सरकार की अपनी आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य अनिवार्य खर्चों में चला जाये। इसलिए अब बहस केवल कर्ज की रकम पर नहीं, कर्ज की उत्पादकता पर होनी चाहिए। हिमाचल में सरकार-दर-सरकार आरोप लगाने के बजाये पिछले दशकों की वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि किस दौर में कितनी उधारी हुई, उसका कितना हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्तियों पर लगा, कितनी परियोजनाओं से वास्तविक आय पैदा हुई और कितना खर्च ऐसा था जिसने भविष्य में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-से फैसले प्रदेश की आर्थिक क्षमता बढ़ाने वाले थे और किन फैसलों का वित्तीय बोझ आज भी बजट पर बना हुआ है। हर बड़ी उधारी का उद्देश्य, अपेक्षित आर्थिक लाभ और भुगतान की क्षमता स्पष्ट होनी चाहिए। हिमाचल कि जनता को यह बताने की जरूरत नहीं कि कर्ज कितना बढ़ा। उसे यह बताना होगा कि दशकों की उधारी ने प्रदेश को कितना मजबूत किया, अपनी आय क्यों पर्याप्त नहीं बन सकी और आज भी नई उधारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही सवाल हिमाचल की आर्थिक नीतियों और सत्ता में रही सरकारों की जवाबदेही तय करेगा।

इस्लाम में बच्चों की परवरिश का बेहतर तरीका है 7-7-7 पैरेंटिंग फ्रेमवर्क



गौतम चौधरी

बच्चों की परवरिश केवल परिवार की निजी जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी नई पीढ़ी को किस तरह तैयार करता है। इस्लामी परंपरा में बच्चों की परवरिश को एक बड़ी अमानत और जिम्मेदारी माना गया है। माता-पिता का दायित्व केवल बच्चों की भौतिक जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि उनके चरित्र, नैतिकता, आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना भी है।

इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज में प्रचलित 7-7-7 पैरेंटिंग फ्रेमवर्क एक दिलचस्प अवधारणा है। इसके अनुसार बच्चे के विकास को लगभग तीन सात-सात वर्षीय चरणों में समझा जाता है। पहले सात वर्ष प्रेम, ममता और खेल के हैं। अगले सात वर्ष शिक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारी के हैं। अंतिम सात वर्ष दोस्ताना संवाद, विश्वास, सलाह और जीवन के लिए तैयार करने के हैं।

यहां एक तथ्यात्मक सावधानी जरूरी है। 7-7-7 मॉडल को पैगंबर मुहम्मद की प्रमाणित हदीस के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। यह एक प्रचलित इस्लामी parenting framework है, जिसे आम तौर पर हज़रत अली से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इसे इसलिए एक उपयोगी व्याख्यात्मक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, न कि इस्लाम का कोई अनिवार्य धार्मिक नियम।

बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके व्यक्तित्व के निर्माण की बुनियाद रखते हैं। इस उम्र में बच्चे को केवल आदेश और अनुशासन की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रेम, सुरक्षा, ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है।

इस्लामी परंपरा में बच्चों के प्रति स्नेह को विशेष महत्व दिया गया है। सहीह बुखारी में वर्णित है कि पैगंबर मुहम्मद ने हज़रत हसन को चूमा और बच्चों के प्रति दया और ममता को महत्व दिया। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने बच्चों को चूमने पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति को दया के महत्व की याद दिलाई।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी परवरिश में प्रेम और अनुशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। बच्चे को पहले यह अनुभव होना चाहिए कि उसका घर उसके लिए सुरक्षा और स्नेह का स्थान है।

यही भावनात्मक आधार आगे चलकर आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और सामाजिक व्यवहार के विकास में मदद कर सकता है।

लगभग सात वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को धीरे-धीरे जिम्मेदारियों से परिचित कराने की आवश्यकता बढ़ती है। इस्लामी परंपरा में नमाज़ के संदर्भ में सात वर्ष की उम्र का विशेष उल्लेख मिलता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस में बच्चों को सात वर्ष की उम्र से नमाज़ का आदेश देने की बात कही गई है।

इससे 7-7-7 मॉडल के दूसरे चरण को एक धार्मिक संदर्भ मिलता है, हालांकि दोनों को बिल्कुल समान मान लेना उचित नहीं होगा।

इस उम्र में बच्चे को केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सत्य बोलना, अमानतदारी, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, धैर्य, संयम, परिश्रम और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों से परिचित कराया जा सकता है।

अनुशासन का अर्थ केवल दंड नहीं है। स्वस्थ अनुशासन का अर्थ है बच्चे को यह समझाना कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसे अपने काम स्वयं करने, समय का सम्मान करने और अपने व्यवहार के परिणामों को समझने की आदत डालना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

लगभग चौदह वर्ष के बाद बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस उम्र में उसके भीतर स्वतंत्र व्यक्तित्व और अपनी राय बनाने की क्षमता तेजी से विकसित होती है। इसलिए माता-पिता की भूमिका भी बदलनी चाहिए।

अब केवल आदेश देने के बजाय संवाद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे की बात सुनना, उसके प्रश्नों को गंभीरता से लेना और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे शामिल करना उसके भीतर जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सकता है।

यही 7-7-7 मॉडल का तीसरा पक्ष है। माता-पिता का केवल नियंत्रक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और विश्वसनीय साथी बनना।

इसका अर्थ यह नहीं कि किशोर को पूरी तरह बिना दिशा के छोड़ दिया जाए। स्वतंत्रता के साथ विवेकपूर्ण मार्गदर्शन आवश्यक है। माता-पिता को सीमा, जिम्मेदारी और विश्वास के बीच संतुलन बनाना होता है।

बच्चे की परवरिश का प्रभाव परिवार की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। परिवार समाज की पहली पाठशाला है। जो बच्चा घर में सत्य, न्याय, अनुशासन, करुणा और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखता है, उसके सार्वजनिक जीवन में भी इन मूल्यों के प्रभाव की संभावना बढ़ती है।

यहीं से 7-7-7 मॉडल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जा सकता है। राष्ट्र निर्माण केवल बड़े-बड़े संस्थानों, कानूनों और आर्थिक योजनाओं से नहीं होता। इसके पीछे ऐसे नागरिक भी होते हैं जो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ईमानदार कर्मचारी, जिम्मेदार व्यापारी, संवेदनशील शिक्षक, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, सामाजिक रूप से जागरूक युवा और कानून का सम्मान करने वाले नागरिक इन सबकी बुनियाद कहीं न कहीं पारिवारिक संस्कारों में तैयार होती है।

इस दृष्टि से बच्चों को देश के प्रति जिम्मेदारी, सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान, कानून के पालन, सामाजिक सद्भाव और दूसरे समुदायों के अधिकारों के सम्मान की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है।

हालांकि यहां भी एक अंतर समझना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण का विचार आधुनिक नागरिक जीवन का व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ है। इसे सीधे किसी एक धार्मिक parenting सूत्र का मूल उद्देश्य बताना ऐतिहासिक रूप से सावधानी की मांग करता है। लेकिन इस्लामी नैतिक मूल्योंन्याय, अमानतदारी, जिम्मेदारी, दया और पड़ोसी के अधिकारो को आधुनिक नागरिकता के मूल्यों से जोड़ा जा सकता है।

आज बच्चों की परवरिश पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो गई है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा और बदलती पारिवारिक संरचना ने माता-पिता के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं।

ऐसे समय में 7-7-7 म डल की सबसे उपयोगी बात शायद इसकी संख्या नहीं, बल्कि इसका क्रमिक दृष्टिकोण है।

छोटे बच्चे को प्रेम चाहिए। बड़े होते बच्चे को दिशा और अनुशासन चाहिए। किशोर को संवाद, सम्मान और विश्वास चाहिए।

इसका अर्थ यह भी नहीं कि सातवें, चौदहवें या इक्कीसवें जन्मदिन पर माता-पिता की भूमिका अचानक बदल जानी चाहिए। हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है। इसलिए सात-सात वर्ष को कठोर नियम के बजाय एक व्यापक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

आखिरकार किसी भी समाज की शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या सैन्य क्षमता में नहीं होती। उसकी वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों के चरित्र में भी दिखाई देती है।

इस्लामी परवरिश का मूल उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान बनाए रखना नहीं, बल्कि नैतिक और जिम्मेदार इंसान तैयार करना भी है। प्रेम से भावनात्मक सुरक्षा, शिक्षा से चरित्र और अनुशासन, तथा विश्वास और संवाद से जिम्मेदारी विकसित करने की कोशिश की जाए तो परिवार समाज के लिए बेहतर नागरिक तैयार कर सकता है।

7-7-7 मॉडल को इसी व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह आधुनिक parenting पर एक उपयोगी विमर्श प्रस्तुत करता है। इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ माता-पिता और बच्चे के रिश्ते का स्वरूप भी बदलना चाहिए।

एक सुरक्षित बचपन, संस्कारित किशोरावस्था और जिम्मेदार युवावस्था मिलकर ऐसे नागरिक तैयार कर सकती है जो अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने दायित्व को समझें।

क्योंकि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता। राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र से बनता है। और नागरिक के चरित्र की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है।

एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों से सफर हुआ आरामदायक

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच से प्रदेश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल के सुपरिणाम अब मंडी में भी नजर आ रहे हैं। जिला के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं। इनके संचालन से जहां यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आय बढ़ाने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम की परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में इससे ऊर्जा लागत में लगभग 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर तक की बचत हो रही है। ईंधन एवं परिचालन व्यय में कमी के साथ-साथ इससे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समग्र दक्षता में भी सुधार हो रहा है।

'महत्वपूर्ण रूट पर मिल रही इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा'

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 17 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला को 25 ई-बसों की सौगात दी थी। इसके बाद जिला में नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अनेक महत्वपूर्ण रूट पर किया जा रहा है। इनमें लंबी दूरी की मंडी-शिमला, मंडी-पालमपुर, मंडी-शिमला-तुलाह, मंडी-चंडीगढ़ के साथ ही लोकल रूट मंडी-सुंदरनगर, मंडी-बटाहर, मंडी-तांदी, मंडी-पाली, मंडी-रोपा, मंडी-रिवालसर-नैनादेवी, मंडी-कोट, मंडी-कोटली, मंडी-माहन तथा मंडी-दुर्गापुर इत्यादि शामिल हैं।

'यात्रियों को भा रही शांत और आरामदायक सवारी'

इलेक्ट्रिक बसों को लेकर यात्रियों में उत्साह है। मंडी के ज्वालापुर निवासी इंद्र ठाकुर ने मंडी से शिमला की यात्रा इलेक्ट्रिक बस में की और अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफर बहुत अच्छा और आरामदायक रहा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार।

वंशिका जम्वाल ने मंडी से दुर्गापुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस में सफर को सुखद अनुभव बताया। यह बस सामान्य बसों की तुलना में काफी बेहतर है और सीटें भी आरामदायक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और अधिक रूट पर किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिल सके।

वहीं जसवंत कुमार ने मंडी से तुलाह तक इलेक्ट्रिक बस में सफर पर कहा कि बस में बैठने के बाद किसी तरह का शोर महसूस नहीं होता और यात्रा काफी आरामदायक रहती है। उन्होंने इस सुविधा के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

कोटली निवासी किरण राणा ने इलेक्ट्रिक बसों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने आम जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है। सीटें आरामदायक होने से यात्रा अनुभव बेहतर हो जाता है।

'मंडी इकाई में 11.34 लाख की बचत'

निगम के बेड़े में शामिल पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें अब मुनाफे का सौदा साबित हो रही हैं। हरित राज्य के संकल्प को गति देते हुए निगम की मंडी और सुंदरनगर इकाइयों ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से महज 24 दिनों के भीतर लाखों रुपये की बड़ी वित्तीय बचत दर्ज की है। निगम के मंडलीय प्रबंधक उत्तम सिंह के अनुसार, 17 अगस्त, 2026 से 10 सितम्बर, 2026 की अवधि में दोनों डिपो में इलेक्ट्रिक बसों का प्रदर्शन शानदार रहा है।



मंडी डिपो के तहत इस अवधि में 60,060 किलोमीटर की दूरी इन 15 बसों ने तय की, जिस पर कुल चार्जिंग खर्च 7,95,795 रुपए आया। इन्हीं रूटों पर पहले पारंपरिक डीजल बसें चलाई जा रही थी, तो इतने ही दूरी पर ईंधन का कुल खर्च 19,30,055 रुपए बैठ रहा था। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से मंडी इकाई को 11,34,260 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

'सुंदरनगर इकाई में भी चमका राजस्व'

सुंदरनगर डिपो में भी 10 इलेक्ट्रिक बसों ने कुल 35,044 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान बिजली चार्जिंग पर मात्र 2,10,037 रुपए का खर्च आया, जबकि डीजल बसों के संचालन पर ईंधन का व्यय 10,07,732 रुपए हो रहा था। सुंदरनगर इकाई को भी 7,97,695 रुपए का बंपर लाभ प्राप्त हुआ है।

'पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता'

निगम प्रबंधन के मुताबिक, दोनों इकाइयों को मिलाकर निगम ने इस अल्प अवधि में कुल 19,31,955 रुपए की बचत की है। डीजल के मुकाबले बिजली की कम लागत और शून्य प्रदूषण के कारण ये बसें पर्यावरण अनुकूल भी साबित हो रही हैं। निगम का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा बढ़ाना है।

'चार्जिंग ढांचा भी हो रहा मजबूत'

इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए जिले में चार्जिंग अवसंरचना को भी विकसित किया जा रहा है। मंडी बस स्टैंड और मंडी वर्कशॉप तथा सुंदरनगर बस स्टैंड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जबकि जंजैहली में प्रस्तावित है। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

'पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम'

इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार केवल परिवहन सुविधा में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। इन बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार के प्रयासों से तकनीक और मूल्य संवर्धन की राह पर एचपीएमसी

* **डिजिटल एमआईएस से पारदर्शी खरीद व्यवस्था, प्रसंस्करण और भंडारण पर बल**
* **एचपीएमसी ने 2025-26 में दर्ज किया 214.19 करोड़ रुपये का कारोबार**

हिमाचल प्रदेश में सेब केवल एक फल नहीं, बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य के हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है और इसके इर्द-गिर्द परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन जैसी अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं। हिमाचल में बागवानी को मजबूत करना केवल उत्पादन बढ़ाने का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बागवानी क्षेत्र में उत्पादन से लेकर विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर बल दे रही है। राज्य सरकार का प्रयास यह है कि बागवान की उपज केवल मंडी में पहुंचने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके बाद होने वाली प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन गतिविधियों में भी बेहतर आर्थिक अवसर सृजित हों।

इस दिशा में हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) की भूमिका लगातार विस्तृत हो रही है। पारंपरिक खरीद व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए निगम ने मण्डी मध्यस्थता योजना (एमआईएस)-2026 के दौरान सेब खरीद प्रक्रिया को एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली से जोड़ा है। इस व्यवस्था में बागवानों के ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर खरीद से संबंधित विवरण दर्ज करने तक की प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रिया को कम करना नहीं, बल्कि खरीद से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, निगरानी को बेहतर बनाना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है।

इस वर्ष अभी तक एचपीएमसी ने एमआईएस-2026 के अंतर्गत बागवानों से 4,188.504 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। यह खरीद निर्धारित 12 रुपये प्रति किलोग्राम के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी उत्पादन अनेक भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में खरीद प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ना रिकॉर्ड प्रबंधन और संस्थागत खरीद व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने में सहायक हो सकता है।

हालांकि, बागवानी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां केवल खरीद तक सीमित नहीं हैं। बागवान के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्पाद को बेहतर बाजार मिले, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जाए और फल से अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। इसी सोच के साथ एचपीएमसी की गतिविधियां अब पारंपरिक खरीद से आगे बढ़कर प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, बागवानी इनपुट और मूल्य संवर्धित उत्पादों तक विस्तृत हो रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से उपज के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ किसानों को बाजार से जोड़ने और बागवानी उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाने की संभावनाएं विकसित हो रही हैं।

सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को केवल ताजा फल के रूप में बाजार में भेजने के बजाय उनसे जूस और अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने से उपज के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। इसी तरह वैज्ञानिक भंडारण और पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में इसका महत्व और बढ़ जाता है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन, भंडारण और बाजार तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियां बनी रहती हैं।

राज्य सरकार सेब के कचरे के वैज्ञानिक उपयोग और मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी बल दे रही है। इसका उद्देश्य बागवानी उत्पादों की बर्बादी कम करने के साथ-साथ प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बागवानी अर्थव्यवस्था में नए आयाम जोड़ना है।

सेब कारोबार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम 'यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली' की शुरुआत है। इसके तहत सेब की पैकिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप 20 किलोग्राम के यूनिवर्सल कार्टन में की जाती है, जिसमें विभिन्न ग्रेड के लिए आवश्यक विनिर्देश तय किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य पैकिंग में होने वाली विसंगतियों को कम करना, लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और बागवानों के हितों की रक्षा करना है। डिजिटल खरीद व्यवस्था के साथ यूनिवर्सल पैकेजिंग सेब की पूरी मूल्य श्रृंखला में जवाबदेही को और मजबूत करती है।

एचपीएमसी की बदलती भूमिका उसके वित्तीय प्रदर्शन में भी दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने लगभग 214.19 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया और करीब 12 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। निगम के कारोबार में विभिन्न गतिविधियों का योगदान रहा। जूस और प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री से लगभग 19.17 करोड़ रुपये, बागवानी इनपुट से करीब 18.50 करोड़ रुपये तथा कोल्ड स्टोरेज और पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाओं से लगभग 6.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। वहीं एमआईएस से संबंधित कारोबार लगभग 158 करोड़ रुपये रहा। ये आंकड़े एचपीएमसी की गतिविधियों में आए विविधीकरण को दर्शाते हैं, जहां खरीद के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण, इनपुट आपूर्ति और मूल्य संवर्धन भी निगम के कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं।

एमआईएस-2026 में डिजिटल खरीद प्रणाली का सफल संचालन इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तकनीक ने खरीद प्रक्रिया को अधिक संरचित बनाने का अवसर दिया है, जबकि एचपीएमसी की प्रसंस्करण और भंडारण संबंधी गतिविधियां बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा तकनीक, संस्थागत समर्थन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर दिया जा रहा बल हिमाचल की बागवानी को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। बागीचे से बाजार तक की पक्रिया जितनी अधिक संगठित, पारदर्शी और मूल्य-सृजन पर आधारित होगी, उतनी ही अधिक संभावनाएं हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था के विस्तार की बनेंगी। डिजिटल खरीद से लेकर प्रसंस्करण और भंडारण तक उठाए जा रहे कदम इसी व्यापक परिवर्तन की आधार भूमि तैयार कर रहे हैं, जहां सेब केवल खेत से बाजार तक पहुंचने वाला उत्पाद नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्यम और अतिरिक्त आर्थिक मूल्य पैदा करने का माध्यम भी बन सकता है।

चिट्टा बेचने वालों के लिए हिमाचल में कोई जगह नहीं: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में चिट्टा बेचकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि



नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इससे बाहर निकालने के लिए संवेदनशीलता के साथ मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ऊना में एंटी-चिट्टा जन-जागरूकता वॉकथॉन की अगुवाई की। इंदिरा स्टेडियम से शुरू हुई वॉकथॉन में जिलेभर से विद्यार्थियों और लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को एंटी-चिट्टा शपथ भी दिलाई।

सुक्खू ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या सरकार के भरोसे नहीं जीती जा सकती। परिवार, शिक्षक, दोस्त और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने युवाओं से अपने साथियों में व्यवहार में होने वाले बदलाव पर नजर रखने और उन्हें नशे से दूर रखने की अपील की। चिट्टा बिकने की विश्वसनीय सूचना 112 पर देने का आहवान करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करीब नौ महीने पहले एंटी-चिट्टा अभियान शुरू किया था और प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ समाज की एकजुटता ही इस अभियान को मजबूत करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर को ऊना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की। उन्होंने 3.87 करोड़ रुपये से बने बहुमंजिला खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण और 9.55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रामपुर पुल का शिलान्यास भी किया।

नेपाल बाढ़ में लापता ऊना के इंजीनियर की तलाश तेज करने का भरोसा

शिमला/शैल। नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता ऊना निवासी इंजीनियर सुखविंदर रतन के परिवार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर उनकी तलाश में मदद की मांग की। परिजनों ने बताया कि 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद से सुखविंदर रतन से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने परिवार को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सुखविंदर रतन की तलाश में तेजी लाने का मामला केंद्र सरकार के सामने उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जल्द जानकारी जुटाने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे और मुश्किल की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है।

सुखविंदर रतन नेपाल में 216 मेगावाट की अपर त्रिशूली जलविद्युत परियोजना में साइट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। 26 अगस्त को क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद से वह लापता हैं। परिवार लगातार उनकी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है।

बीटल प्रभावित मधुमक्खी पालकों को 30 प्रतिशत राहत

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले में छोटे छत्ते वाले भृंग (एथिना टुमिडा मरे) के प्रकोप से प्रभावित मधुमक्खी पालकों को सरकार 30 प्रतिशत राहत राशि प्रदान करेगी। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत



निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि कांगड़ा, बंडी, नागण, फट और कल्याड़ा क्षेत्रों में बीटल के कारण मधुमक्खी पालकों को नुकसान हुआ है। यह बीटल मधुमक्खी के बक्सों में लारवा छोड़ता है, जिससे कुछ ही दिनों में शहद और पूरी कॉलोनी प्रभावित हो जाती है।

मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित पालकों को राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहद की बिक्री के लिए बिग बास्केट के माध्यम से विपणन की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों और बागवानों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। बैठक में निदेशक बागवानी सतीश कुमार सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

रेणुका जी में 28.22 करोड़ की पांच सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास

पीएमजीएसवाई-4 के तहत बनेंगी सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के तहत पांच सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 28.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परियोजनाओं में बिरला-गाटू से मढारा, कटवारी बगराथ से बिरला, ठाकर से कुज्जेवाला, गांव बखान से केलेवाला और खरकोली से उंगर कांडो सड़क शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास की सबसे बड़ी जरूरत हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से श्री रेणुका जी के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। इससे लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने और पुरानी सड़कों में सुधार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को नई सड़क परियोजनाओं के लिए बधाई दी।

सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सिरमौर में इन परियोजनाओं की मंजूरी से ग्रामीण संपर्क व्यवस्था और मजबूत होगी।

कार्यक्रम में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए विशेषज्ञ समिति गठित

शिमला/शैल। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी (एआईएमएसएस), चमियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर गठित यह समिति प्रत्येक संस्थान में दो से चार ऐसे विभागों की पहचान करेगी, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है।

सरकार का उद्देश्य जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के लिए उच्चस्तरीय तथा बहु-विषयक उपचार सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध करवाना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। समिति आधुनिक चिकित्सा तकनीक, बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों, उपकरणों, प्रशिक्षण और वित्तीय जरूरतों का भी आकलन करेगी।

अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के कुलपति डॉ. डी.के. वर्मा समिति के अध्यक्ष होंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. गोपाल बेरी, टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा, एआईएमएसएस चमियाणा के प्रधानाचार्य डॉ. बृज शर्मा, आईजीएमसी शिमला के प्रोफेसर डॉ. बलबीर वर्मा और प्रोफेसर डॉ. पुनीत महाजन सदस्य होंगे। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त/ संयुक्त निदेशक सदस्य सचिव होंगे।

समिति को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में तृतीयक और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इससे चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और लक्षित अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कृषक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिया प्रशिक्षण

शिमला/शैल। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में कृषक



महिलाओं के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की ओर से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि में महिला के तहत यह प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में भड़याड़ा, बुहाणा और टंबर के कस्टम हायरिंग केंद्रों से जुड़ी 25 कृषक महिलाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नए कौशल सिखाकर उन्हें स्वरोजगार और आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना था।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मौसमी फलों और सब्जियों से विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने, बेकरी उत्पाद बनाने, मोमबत्ती बनाने और कुशन कवर तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं को इन उत्पादों को छोटे स्तर पर तैयार कर आय का साधन बनाने की जानकारी भी दी गई।

इसके अलावा उद्यम शुरू करने, उत्पादों की बिक्री और बाजार तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी विपणन रणनीतियों की जानकारी दी गई। जीवन-कौशल प्रबंधन पर भी संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।

सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांता वत्स ने महिलाओं से प्रशिक्षण में सीखे कौशल का उपयोग स्वरोजगार के लिए करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कृषक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने प्रशिक्षण के सफल आयोजन के लिए डॉ. नीना व्यास, डॉ. राज पठानिया, डॉ. सपना गौतम और डॉ. बिंदिया दत्त को बधाई दी।

धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, एमएसपी 2461 रुपये

शिमला/शैल। हिमाचल में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू हो गया है। किसान एचपी एपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने के लिए टोकन बुक कर सकते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि प्रदेश में धान की खरीद 3 अक्तूबर से शुरू होगी और 15 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर में 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इस बार किसानों को एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज किसानों का व्यक्तिगत और जमीन से जुड़ा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा, इसलिए जमीन के सत्यापन के लिए पटवारी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बैंक की पूरी जानकारी किसान को स्वयं भरनी होगी।

जो किसान फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एचपी एपीपी पोर्टल पर पहले की तरह पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। ऐसे किसानों की जमीन का ऑनलाइन सत्यापन पटवारी और फसल की उपज की एंट्री कृषि अधिकारी द्वारा की जाएगी।

भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 72 रुपये अधिक है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल निर्धारित खरीद केंद्रों पर बेचकर एमएसपी का लाभ उठाएं। कृषि अधिकारियों को भी किसानों तक एमएसपी की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

800 करोड़ देकर धौलासिद्ध प्रोजेक्ट वापस लेगी सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध जलविद्युत



परियोजना को एसजेवीएनएल से वापस लेने के लिए 800 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।

नादौन में सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास के बाद जनसभा में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर के दावों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन नहीं है। इसकी मंजूरी 22 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी और केंद्र ने उस समय 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। सुक्खू ने दावा किया कि कॉलेज के निर्माण पर राज्य सरकार ने अपने बजट से 450 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अगले दो महीने में शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जापान के सहयोग से करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर इंस्टीटयूट बनाया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेजों में करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं।

नादौन में 31.19 करोड़ रुपये की लागत से 250 मीटर लंबा डबल लेन सधोड़ा पत्तन पुल बनाया जाएगा। इससे नादौन और ज्वालामुखी की 15 पंचायतों के 30 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन में 400 करोड़ रुपये से ब्यास रिवर फ्रंट और ज्वालामुखी के लुथान में 150 करोड़ रुपये से सुखाश्रय परिसर बनाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की अनदेखी और मौजूदा सरकार को गिराने के प्रयासों का आरोप भी लगाया।

2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप तैयार

नशा मुक्ति केंद्र 334 से बढ़ाकर 1751 करने का लक्ष्य, शिमला में जल्द खुलेगा एनसीबी का जोनल कार्यालय

शिमला/शैल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार किया है। इसकी जानकारी



शुक्रवार को शिमला में पीआईबी की ओर से आयोजित 'वार्तालाप' कार्यक्रम में दी गई। गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने अभियान की रूपरेखा साझा की।

अधिकारियों के अनुसार, रोडमैप में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने, सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशे की रोकथाम और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए चार स्तंभ, 25 घटक और 200 से अधिक कार्य बिंदु तय किए गए हैं।

नशा मुक्ति और पुनर्वास सुविधाओं को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना है। मार्च 2029 तक नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 334 से बढ़ाकर 1751 करने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में नशे के उपचार के लिए अलग विभाग बनाने की योजना है।

अभियान के तहत जागरूकता को भी बढ़ाया जाएगा। अभी करीब 20 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे अभियान को 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के जरिए एक लाख 'नशा मुक्त भारत मित्र' तैयार किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजों को भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में प्रमुख भूमिका दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2027 तक हर राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत किया जाएगा। अभियान की हर तीन महीने में समीक्षा होगी। मादक पदार्थो के नमूनों की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर देने का लक्ष्य भी रखा गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में एनसीबी का जोनल कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। अधिकारियों के अनुसार, कार्यालय जल्द शुरू किया जाएगा।

एआईटीएससी में पीएचएचपी एंड सी निदेशालय का शानदार प्रदर्शन

बालिका दल ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया, कैडेट्स ने जीते 42 पदक

शिमला/शैल। पीएचएचपी एंड सी निदेशालय के कैडेट्स ने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय थल सैनिक कैंप (एआईटीएससी) 2026 में शानदार



प्रदर्शन किया। 31 अगस्त से 12 सितंबर तक चले इस राष्ट्रीय स्तर के कैंप में सीनियर विंग बालिका दल ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया।

बालिका दल ने कुल 32 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। वहीं बालक दल ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 14 पदक अपने नाम किए। इनमें सर्विस शूटिंग में चार स्वर्ण पदक, मैप रीडिंग में एक रजत और नौ कांस्य पदक शामिल हैं। इस तरह निदेशालय के कैडेट्स ने कुल 42 पदक हासिल किए। अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि कैडेट्स की मेहनत, अनुशासन और बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम है।

एआईटीएससी में निदेशालय का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षो में भी मजबूत रहा है। बालक दल ने 2024 और 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया था। वर्ष 2026 में बालिका दल ने ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया।

पदक विजेता कैडेट्स को 14 सितंबर को रोपड़ स्थित एनसीसी अकादमी में मेजर जनरल नरेंद्र सिंह, एसएम, एडीजी एनसीसी, पीएचएचपी एंड सी निदेशालय ने सम्मानित किया। उन्होंने कैडेट्स को बधाई देते हुए उनकी मेहनत और अनुशासन की सराहना की।

एडीजी एनसीसी ने सीडीआर अमृतसर ग्रुप एनसीसी और प्रशिक्षकों की टीम के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कैडेट्स को लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने से यह प्रदर्शन संभव हुआ।

यह सफलता कैडेट्स के साथ-साथ उनके प्रशिक्षकों, एएएनओ, पीआई स्टाफ और निदेशालय की पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

बल्क ड्रग पार्क में काम तेज करने के निर्देश

उद्योग मंत्री ने अधिकारियों से तय समय में परियोजना पूरी करने को कहा

शिमला/शैल। हिमाचल के बल्क ड्रग पार्क की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की उच्च स्तरीय



समिति की बैठक में परियोजना से जुड़े सभी कार्यो को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा।

मंत्री ने अधिकारियों को पार्क से संबंधित सभी टेंडरों को जल्द लागू करने और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी हो और सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें।

बैठक में परियोजना के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क दवा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए राज्य में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को मजबूत करने के साथ नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

उन्होंने कहा कि पार्क में निवेश की संभावनाओं को लेकर जल्द ही प्रमुख दवा कंपनियों के साथ बातचीत की जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियां हिमाचल की इस परियोजना में निवेश के लिए आगे आएं।

बैठक में उद्योग विभाग, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी विभागों को परियोजना की गति बनाए रखने और तय समय सीमा में काम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।

9000 फीट की ऊंचाई पर तिरलोकीनाथ में रग्बी की नई शुरुआत

अंडर-19 खिलाड़ियों की कोचिंग और प्रतिभा चयन शुरू स्कूल गेम्स में ट्रायल आधार पर शामिल हुआ रग्बी

शिमला/शैल। समुद्र तल से 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित तिरलोकीनाथ में अंडर-19 रग्बी खिलाड़ियों के लिए कोचिंग और प्रतिभा चयन शुरू किया गया है। रग्बी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश (आरएएचपी) की पहल के तहत सरकारी स्कूल तिरलोकीनाथ में विद्यार्थियों को रग्बी का प्रशिक्षण दिया गया और लड़के-लड़कियों की अंडर-19 टीमों के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की गई।

आरएएचपी के कोच एवं चयनकर्ता तथा हिमाचल प्रदेश रग्बी टीम के कोच नवप्रीत सिंह ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। यह कार्यक्रम लाहौल में चल रहे स्कूली खेल आयोजन के साथ आयोजित किया गया, जिसमें 19 स्कूलों के करीब 150 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। लड़कों की प्रतियोगिता के बाद लड़कियों का खेल आयोजन 22 सितंबर को होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र में स्कूल गेम्स की अंडर-19 श्रेणी में रग्बी को ट्रायल आधार पर शामिल किया है। इसके तहत जिला स्तर पर टीमों का चयन किया जा रहा है। अक्तूबर में राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता प्रस्तावित है।

इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रग्बी सीखने और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने का अवसर देना है। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा।

लाहौल के एडीपीईओ विनोद कुमार ने पहल का स्वागत करते हुए कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में रग्बी की विशेष कोचिंग पहुंचने से विद्यार्थियों को नए खेल से जुड़ने और अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे अधिक स्कूलों और बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तिरलोकीनाथ समुद्र तल से करीब 2760 मीटर यानी 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्कूली स्तर पर रग्बी प्रशिक्षण और प्रतिभा चयन को खेल के विस्तार की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

रग्बी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के कार्यक्रम में भी शामिल है। एसजीएफआई के 2026 कैलेंडर के अनुसार अंडर-19 लड़कों और लड़कियों की राष्ट्रीय स्कूल रग्बी प्रतियोगिता 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में प्रस्तावित है।

रग्बी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. विकास सूद ने कहा कि तिरलोकीनाथ में कार्यक्रम के बाद लाहौल-स्पीति के स्कूलों से रग्बी प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भाजपा में अंदरूनी दरारें सतह पर

शिमला/शैल। हिमाचल में सुक्खू सरकार को घेरने के लिए भाजपा के पास मुद्दे हैं, नेता हैं और विधानसभा में सरकार को घेरने का मंच भी है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी के भीतर से उठती आवाजें अब खुद भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। मंडी में भाजपा विधायक अनिल शर्मा का अपनी ही पार्टी के सांसदों पर सार्वजनिक हमला महज एक स्थानीय विवाद नहीं है। यह उस असहजता का संकेत है जो अब पार्टी के भीतर बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंच तक पहुंच रही है।

अनिल शर्मा ने कहा कि कोटली पार्किंग के लिए उन्होंने भाजपा सांसदों से 25 – 25 लाख रुपये मांगे, लेकिन अपेक्षित मदद नहीं मिली। इसके बाद वह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास गए और उनके अनुसार करीब दो करोड़ रुपये की राशि मिलने के बाद काम शुरू हुआ। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने के बीच एक भाजपा विधायक का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि अपने सांसदों से मदद नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने काम कर दिया, पार्टी के भीतर तालमेल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विवाद बढ़ने के बाद अनिल शर्मा ने फिर कहा कि वह सुक्खू से पार्टी की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए मिलते हैं –''अपने इलाके के लिए पैसा लाता हूं, चाहे कहीं से मिले।'' राजनीतिक तौर पर इस बयान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भाजपा सरकार को विपक्ष के रूप में घेर रही है, जबकि उसी पार्टी का एक विधायक विकास के लिए सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से सहयोग लेने को सार्वजनिक रूप से सही ठहरा रहा है। भाजपा के सामने सवाल केवल यह नहीं है कि अनिल शर्मा ने क्या कहा। सवाल यह है कि पार्टी के विधायक और सांसद एक – दूसरे के साथ किस स्तर पर खड़े हैं? यदि स्थानीय विकास के मुद्दे पर भी सार्वजनिक शिकायतें सामने आने लगें तो प्रदेश स्तर पर सरकार के खिलाफ बनाई जा रही एकजुट राजनीतिक लाइन कितनी मजबूत रहेगी?

भाजपा की अंदरूनी राजनीति की दूसरी परत कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए नेताओं से जुड़ी है। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। लेकिन इन नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में भाजपा की अपनी पुरानी चार्जशीट का हवाला देकर पलटवार किया। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने पहले ही सुधीर शर्मा, हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे और अब उन्हीं मामलों की जांच होने पर भाजपा सवाल उठा रही है। इससे कांग्रेस को भाजपा के भीतर आए नेताओं के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड को ही भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर जरूर मिल रहा है।

सुधीर शर्मा का विजिलेंस प्रकरण भी इसी टकराव को और राजनीतिक बनाता है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है और जांच एजेंसी ने आय, संपत्ति, निवेश तथा निर्माण से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सुधीर शर्मा और भाजपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध में की गई कारवाई बताया है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व की एकरूपता का है। एक तरफ जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जैसे नेता अपने – अपने मुद्दों पर सरकार से भिड़ रहे हैं। मंडी से अनिल शर्मा अपने ही सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर भी समय – समय पर अलग – अलग राजनीतिक संकेत सामने आते रहे हैं।

यही भाजपा की असली राजनीतिक परीक्षा है। क्या प्रदेश भाजपा के पास सरकार विरोधी एक साझा कमान है या अलग – अलग नेता अपनी – अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और मजबूत करने में लगे हैं?

मंडी की घटना ने इस सवाल को और तीखा कर दिया है। चार भाजपा सांसदों वाले प्रदेश में भाजपा विधायक का सांसदों से मदद न मिलने की बात कहना केवल धन की मांग का विवाद नहीं रह जाता। यह पार्टी के भीतर जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और राजनीतिक तालमेल की परीक्षा बन जाता है। खासकर तब, जब उसी विधायक की ओर से मुख्यमंत्री सुक्खू के सहयोग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जा रहा हो। भाजपा के पास सुक्खू सरकार को घेरने के लिए कर्ज, रोजगार, कर्मचारी – पेंशनर, स्वास्थ्य, विकास और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं। लेकिन विपक्षी राजनीति में सरकार की कमजोरियां गिनाना और उन्हें एक प्रभावी राजनीतिक अभियान में बदलना दो अलग बातें हैं। जब पार्टी के भीतर से ही अलग – अलग आवाजें निकलें, तो सरकार के खिलाफ बनाई गई धार का राजनीतिक असर बिखर सकता है।

कांग्रेस के लिए यह स्थिति राजनीतिक अवसर जरूर बनाती है, लेकिन इससे सरकार के खिलाफ मौजूद मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। असली सवाल भाजपा की क्षमता का है कि वह इन मुद्दों को किस तरह एक साझा विपक्षी अभियान में बदलती है।

फिलहाल तस्वीर साफ है ''सरकार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई और भाजपा के भीतर नेताओं की अपनी – अपनी लड़ाई।'' मंडी ने इसे सार्वजनिक कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक विधायक का स्थानीय असंतोष है या प्रदेश भाजपा के भीतर बढ़ती राजनीतिक खींचतान का बड़ा संकेत।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा को नजरअंदाज नहीं कर सकती सरकार

नियमों के तहत भर्ती कर्मचारियों की पुरानी सेवा भी मानी जाएगी वरिष्ठता, पेंशन और वेतन बढ़ोतरी के लाभ देने के आदेश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अदालत ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती तय नियमों और चयन प्रक्रिया के तहत हुई है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट पर की गई सेवा को बाद में नियमित करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी सेवा को वरिष्ठता, पेंशन और वेतन बढ़ोतरी जैसे लाभों के लिए गिना जा सकता है।

लोकश शर्मा व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य मामले में हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2018 से नियमित मानने का आदेश दिया है। ये पीजीटी शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति 2 दिसंबर 2014 को तय भर्ती नियमों के तहत चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी।

इन शिक्षकों ने तीन साल की सेवा पूरी की। इसके बाद सरकार ने उन्हें 2 जून 2018 से नियमित किया। शिक्षकों ने अदालत में कहा कि उनकी नियुक्ति सामान्य चयन प्रक्रिया के जरिए हुई थी। इसलिए उनकी सेवा की शुरुआत 2014 से ही मानी जानी चाहिए और उन्हें उसी आधार पर वरिष्ठता तथा दूसरे सेवा लाभ मिलने चाहिए।

मामले में बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए पीटीए – जीआईए शिक्षकों का मामला भी सामने आया। इन शिक्षकों को जनवरी 2015 में कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया था, लेकिन उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित कर दिया गया था। जबकि लोकश शर्मा और अन्य शिक्षकों की नियुक्ति इससे पहले दिसंबर 2014 में हुई थी।

हाईकोर्ट ने इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं को भी 1 अप्रैल 2018 से नियमित करने का आदेश दिया। साथ ही उनकी वरिष्ठता 2 दिसंबर 2014 से मानी जाएगी। उनकी पुरानी सेवा को पेंशन के लिए भी गिना जाएगा और नियमों के अनुसार वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

हालांकि, अदालत ने पिछली पूरी अवधि का पैसा देने का आदेश नहीं दिया है। याचिका देर से दाखिल होने के कारण शिक्षकों को 4 फरवरी 2023 से वास्तविक आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे पहले की अवधि सेवा और दूसरे लाभों की गणना में मानी जाएगी, लेकिन उसका पूरा बकाया पैसा नहीं मिलेगा।

फैसले का असर वरिष्ठता पर भी पड़ेगा। जिन कर्मचारियों को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है, उन्हें केवल इस फैसले के कारण पद से नीचे नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन कर्मचारियों की पदोन्नति अभी नहीं हुई है और उनकी वरिष्ठता बदलती है, उनके मामलों में नई वरिष्ठता के आधार पर आगे की कारवाई करनी होगी।

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले का लाभ हर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के मामले में है जिनकी भर्ती तय नियमों और सही चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी। इसलिए दूसरे मामलों में कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा की स्थिति को अलग से देखा जाएगा।

अदालत ने अपने फैसले में 25 अप्रैल 2026 के देविंदर कुमार मामले का भी उल्लेख किया है। उस मामले में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े राज्य के कानून को रद्द किया गया था।

फैसले से साफ है कि नियमों के तहत चयनित कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट सेवा को केवल इसलिए खत्म नहीं माना जा सकता कि उसे बाद में नियमित किया गया। अब ऐसी सेवा को वरिष्ठता, पेंशन और वेतन बढ़ोतरी जैसे लाभों के लिए भी महत्व मिलेगा।